संगठन के कार्य और कर्तव्य

संगठन के कार्य और कर्तव्य

प्रस्तावना

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सरकारी क्षेत्र में एकीकृत सेवाओं और वैश्विक समाधानों, ई-शासन / ई-शासन समाधानों के लिए सर्वोत्तम उपाय प्रदान करने वाला, 1976 में स्थापित भारत सरकार का एक प्रमुख वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थान है।

वर्ष 1975 में, भारत सरकार ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों में योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कंप्यूटर आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (सूचना-विज्ञान-के नेतृत्व वाले विकास) हेतु सूचना प्रणाली के विकास और सूचना संसाधनों के उपयोग के लिए भी आर्थिक और सामाजिक विकास रणनीतिक रूप से प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया। इसके पश्चात् केंद्र सरकार ने 1976 में उच्च प्राथमिकता आयोजना की परियोजना राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और बाद में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को वित्तीय सहायता के साथ यू एस $ 4.4 मिलियन पर ध्यान आकर्षित किया।

एनआईसी शुरू में तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक्स आयोग / इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग (डीओई) सूचना, योजना और विश्लेषण समूह (आईपीएजी) के दायरे में स्थापित किया गया था। 1987, में इसे केंद्रीय योजना आयोग और अक्टूबर 1999 में नवगठित केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था जो बाद में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बन गया।

एनआईसी के जनादेश पर भारत सरकार के संकल्प को 2 सितंबर 1995 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। परियोजनाओं के प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र नीचे दिए गए हैं।

एनआईसी को राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों / परियोजनाओं / प्रचार संबंधी गतिविधियों का प्रभार आधार पर समर्थन करने के लिए अपनी सेवाओं, विशेषज्ञता और असंरचना जिसमें निकनेट भी शामिल है का उपयोग करने की अनुमति है।

एनआईसी / निकनेट के सूचना-विज्ञान और नेटवर्क समर्थन को विशिष्ट प्रचार गतिविधियों / परियोजनाओं / कार्यक्रमों में लगे सार्वजनिक और निजी संगठन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

निर्दिष्ट संगठनों और प्रचार अनुप्रयोगों के लिए एनआईसी / निकनेट की सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, विशेषज्ञता और आधारभूत संरचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक्सेस की निर्दिष्ट श्रेणियों की अधिगम की अनुमति है।

एनआईसी / निकनेट को पहचाने गए कार्य-क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियों / परियोजनाएं / कार्यक्रमों के समर्थन के लिए सक्षम सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

उपलब्धियां

एनआईसी एक चौथाई सदी से अधिक की अवधि के दौरान सतत विकास के साथ ही डिजिटल अवसरों के प्रवर्तक तथा सरकारी क्षेत्र (राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय जिलों) में ई-शासन / ई-शासन अनुप्रयोगों के "मुख्य निर्माता" के रूप में उभरा है। एनआईसी के पास आईसीटी नेटवर्क "एनआईसीएनईटी" के माध्यम से केंद्र सरकार के विभागों / मंत्रालयों, 28 राज्य सरकारों, 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 6 केंद्र शासित प्रदेशों और भारत के लगभग 600 जिला प्रशासन सभी के साथ संस्थागत संबंध हैं। एनआईसी ने खंडों, जिला, राज्यों और केंद्र में सरकारी मंत्रालयों / विभागों में सरकारी सेवाओं में सुधार, व्यापक पारदर्शिता को

बढ़ाने विकेंद्रीकरण, योजना और प्रबंधन, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को बेहतर दक्षता और जवाबदेही की सुविधा प्रदान करने में ई-शासन / ई-शासन अनुप्रयोगों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एनआईसी सरकार के "सूचना-विज्ञान प्रेरित-विकास" कार्यक्रम (जिसे ई-सरकार कार्यक्रम, ई-शासन कार्यक्रम भी कहा जा सकता है) में एक सक्रिय उत्प्रेरक और सुविधाकार रहा है, जो उसे सामाजिक और सार्वजनिक प्रशासनों में आईसीटी अनुप्रयोगों को लागू करके 'भारत में पहुंच' बनाने तथा इसके साथ-साथ प्रतियोगी लाभ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है जिन्हें निम्न से देखा जा सकता हैः-

- पंचवर्षीय योजना अवधि (अर्थात् 1972-77) में केंद्र सरकार का सूचना-विज्ञान विकास कार्यक्रम
- 1980 तथा 1990 के दौरान केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में इंटरनेट/इंट्रानेट अधिगम तथा संसाधन भागेदारी हेतु "निकनेट" गेटवे।
- सातवीं योजना अवधि (अर्थात् 1985-1990) में राज्य सरकार का सूचना-विज्ञान विकास कार्यक्रम
- जिला प्रशासन के लिए डिसनिक एक निकनेट आधारित जिला सरकार का सूचना-विज्ञान कार्यक्रम
- क्षेत्रीय तथा सामाजिक-आर्थिक विकासों से बदलती हुई कृषि-जलवायु विषयक स्थितियों, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से देश के सभी जिलों तक " इंटरनेट" प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले 1985-90 के दौरान भारत पहुँचना।
- निकनेट प्रचालनों को व्यवस्थित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित आईनॉक (आईएनओसी) एकीकृत नेटवर्क प्रचालन केंद्र।
- एकीकृत डॉटा केंद्र, जो अत्याधुनिक मूल संरचना सुविधा से युक्त एक विश्व व्यापी डॉटा केंद्र है, जिसमें व्यापक श्रेणी की प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हुए 1000 से भी अधिक हाई-एंड सर्वरों को रखने की क्षमता है।
- डिजिटल प्रमाणन प्राधिकरण और सार्वजनिक कुंजी बुनियादी ढांचे की स्थापना (पीकेआई)।
- हैदराबाद में आपदा वसूली सेंटर (डीआरसी) की स्थापना।

पिछले 27 वर्षों के दौरान, एनआईसी ने अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर उपकरण का उपयोग करते हुए विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कई "नेटवर्क केंद्रित" अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कार्यान्वित किये हैं।

रीचिंग-आउट-इन्टो" और "पहुंचने-वाली" अवधारणाओं का प्रयोग किया गया और उसे देश में इंटरनेट प्रौद्योगिकी शुरू करने से पहले जिला मुख्यालयों में स्थित अपने 600 निकनेट नोड्स के माध्यम से अपने विभिन्न आईसीटी प्रसारण परियोजनाओं के माध्यम से एनआईसी द्वारा परिचालित किया गया। 1980 के दशक और 1990 के शुरुआती भाग के दौरान, सरकारों में विकास योजना तथा अनुकूल प्रशासन का विकास करने (अर्थात् वर्तमान दिन का एक पुराना संस्करण "ई-शासन" / "ई-सरकार") के लिए "निर्णय समर्थन प्रणाली" बनाने की नीति पर जोर दिया।

एनआईसी के पास जन प्रशासन और शासन के क्षेत्रों में जैसे कृषि और खाद्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और पर्यावरण, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बजट और कोषागार खजाना, वित्तीय संसाधन, परिवहन, जल संसाधन, न्यायालय प्रबंधन, ग्रामीण विकास, भूमि अभिलेख और संपत्ति पंजीकरण, संस्कृति और पर्यटन, आयात और निर्यात सुविधा, सामाजिक कल्याण सेवाएं, सूक्ष्म स्तर की योजना आदि के क्षेत्रों में जनता विभिन्न ई-सरकारी परियोजनाओं का संचालन डिजाइन, विकास और उनके परिचालन में विशाल कोर विशेषज्ञता और अनुभव है।

एनआईसी ने केंद्रीय और मुख्य रूप से प्रायोजित क्षेत्र कार्यक्रमों में निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को कार्यान्वित करके जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सूचना क्रांति में एक प्रमुख भूमिका निभाई है :-

- **प्रौद्योगिकी न्यायालय के मामलों में शीघ्र परीक्षणों की सुविधा प्रदान करता है "- कारावास और न्यायालय के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सफल प्रयोग की सुविधा प्रदान करती है, जहां कारावास कॉम्प्लेक्स में परीक्षण चल रहा है और न्यायाधीश अदालत में अंडर-ट्रायल की सुनवाई करते हैं। इस तकनीक से संचालित प्रक्रिया का अनुभव बिहार राज्य में किया गया है तथा अन्य राज्यों में भी इसका बहुविध प्रभाव पड़ा है।**

- "जन शिकायतों का निवारण" - कई अन्य राज्यों में फैली हुई तथा निकनेट पर छत्तीसगढ़ सरकार का एक सतत कार्यक्रम जिसने जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं प्रदान की हैं।
- भारतीय न्यायालयों में सूचना प्रौद्योगिकी - भारत में सर्वोच्च न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों को कवर करने वाली एक ऐतिहासिक परियोजना ।
- एगमार्कनेट - भारतीय कृषि के वैश्वीकरण की दिशा में एक कदम – कृषि उत्पाद बाजार मूल्य सूचना का प्रसार करने के लिए कृषि उत्पाद थोक बाजार (एपीडब्लूएम) की नेटवर्किंग - मार्च 2002 तक 735 एपीडब्ल्यूएम तथा 2002-07 के दौरान अतिरिक्त 2000 एपीडब्ल्यूएम की नेटवर्किंग, कृषि और ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए 7000 एपीडब्ल्यूएम और लगभग 32000 ग्रामीण बाजारों को नेटवर्क करने के लिए सड़क मानचित्र बनाया गया है।
- बिक्री कर प्रशासन – स्टामिना, टेकिस तथा मुद्रा – राज्यों की सफल कहानियां
- ग्रामीण सॉफ्ट – गरीबी उन्मूलन योजनाओं के निगरानी कार्यक्रम में आईसीटी
- मुद्रा – सहकारी बैंक प्रबंधन सॉफ्टवेयर
- स्मार्ट नगरपालिका – नगर निगम प्रशासनों के कार्यों को प्रभावी रूप से करने के लिए आईसीटी रूपरेखा।
- ई-पंचायत – पंचायत प्रशासन हेतु आईसीटी रूपरेखा।
- सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण – व्यवसाय प्रक्रिया को पुनः निर्मित करने के लिए मुख्य आधार।
- पर्यावरण में सूचना प्रौद्योगिकी – पर्यावरण सुरक्षा की तरफ एक कदम।
- पासपोर्ट सेवाएं – भारतीय नागरिक के लिए ई-पासपोर्ट की ओर।
- भारतीय सीमा शुल्क और डीजीएफटी में ईडीआई सेवाएं।
- सरमन – केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व संग्रह के लिए इंट्रानेट समाधान।
- आईटी तथा सड़क परिवहन – भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र में स्मार्ट क्रांतिः सारथी तथा वाहन;
- केंद्रीय सिविल पेंशन – 32500 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखाओं के माध्यम से प्राधिकरण।
- संपदा पंजीकरण - कार्ड, स्टार, पर्ल, कॉर्ड, हरिस, प्रिज्म
- भूमि अभिलेख कम्प्यूटरीकरण - भोमी, भुमी, तमिलनिलम, भूलेख, हिमभूमि, भुईया, अपकाखाता, धरणी, आदि।
- दिल्ली की उपयोगिता मानचित्रण - दिल्ली में स्थानिक योजना के लिए एक उपकरण
- वारना नगर प्रयोग – तार युक्त गांव और प्रवर "स्व-सहायता" आंदोलन; एनआईसी और महाराष्ट्र सरकार, वारना सोसाइटी, प्रवर सोसाइटी की एक संयुक्त उद्यम परियोजना
- ई-ग्रंथालय - "भारत एक ज्ञान समाज" में प्रवेशकों को लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्किंग के लिए एक डिजिटल कार्यसूची।
- बजट और कोषागार का कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम
- पीएओ 2000 - डिजिटल यात्रा "सुधार" को केंद्र सरकार के लगभग 350 वेतन व लेखा कार्यालयों का आधुनिकीकरण करने के लिए 1985 में शुरू किया गया।
- देश भर में डाक / दूरसंचार मंडल स्तर पर लेखा कार्यक्रम (सीपीएसीटी / सीटीएसीटी)
- एचओपीटीएस - देश में भारतीय डाक प्रणाली के 600 एचपीओ में लेनदेन प्रसंस्करण प्रणाली
- ई-डाक सेवा : देश में 156000 डाक घरों में संदेश ई-मेल भेजने / प्राप्त करने में लोगों को सक्षम बनाता है।
- सभी राज्यों में डाक जीवन बीमा (पीएलआई) कम्प्यूटरीकरण परियोजनाएं;
- ग्रामीण बाजार - ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमों के लिए ई-वाणिज्य
- सामुदायिक सूचना केंद्र (सीआईसी) – का उद्देश्य देश के "ग्रामीण" और "दूरस्थ" क्षेत्रों (पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम राज्य) का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है।
- कोषागार प्रणाली - अत्याधुनिक ऑनलाइन कोषागार प्रणाली की उप-कोषागारों तक छत्तीसगढ़ में स्थापना की गई थी।
- कर्नाटक में ग्रामीण विकास सेवाएं (आरडीएस)

- **डीएसीएनईटी - प्रतिकृति के लिए मामले मॉडल के रूप में उभरने और केंद्र सरकार के कृषि और सहयोग विभाग के लिए एक ई-सरकारी परियोजना।**
- **एनरिच - यूनेस्को और एनआईसी का एक सहयोगी आईसीटी फ्रेमवर्क उत्पाद**
- **ई-सरकारी अनुप्रयोगों के लिए स्मार्ट कार्ड प्रौद्योगिकी**
- **कोलाब कैड - एक ओपन स्त्रोत कंप्यूटर समर्थ डिज़ाइन पैकेज**
- **ग्रामसंपर्क – जीआईएस पर आधारित सामाजिक क्षेत्र परियोजना का कार्यान्वयन**
- **डिसनिक - निचले स्तर का विकास करने के लिए जिला सरकार सूचना-विज्ञान विकास कार्यक्रम को 439 जिलों में 1987 के दौरान शुरू किया गया।**
- **इंट्रानिक – प्रभावी जी2ई मॉडल की सुविधा प्रदान करता है तथा मामला अध्ययन के रूप में www.microsoft.com पर दिखाई देता है।**
- **रेस (आरएसीई) (कंप्यूरीकृत ऊर्जा बिलिंग के जरिए राजस्व प्रशासन)**
- **भारत पोर्टल - सूचना और सेवाओं की एकल विंडो वेब आधारित वितरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोर्टल**
- **वैश्विक बाजार सूचना-विज्ञान सेवाएं [संयुक्त राष्ट्र व्यापार बिंदु विकास केंद्र (यूएनटीपीडीसी) द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार अवसर (ईटीओ) प्रणाली के जीटीपीनेट के साथ नेटवर्किंग करते हुए भारतीय व्यापारियों के लिए लगभग165 देशों से संबंधित हैं।]**
- **चिकित्सा सूचना-विज्ञान और दूर-चिकित्सा सेवाएं**
- **ग्रंथसूची सेवाएं, और**
- **बौद्धिक संपदा और ज्ञान-सूचना सेवाएं**
- **मौसम संसाधन सूचना सेवाएं**

"ई-शासन" शुरू करने के संबंध में एक प्रमुख कदम के रूप में, एनआईसी केंद्र सरकार की "ई शासन कार्यसूची" को लागू करने में शामिल हैः-

- अनुभाग अधिकारी स्तर तक इंटरनेट / इंट्रानेट अवसंरचना (पीसी, कार्यालय उत्पादकता उपकरण, व्यापार आवंटन पर पोर्टल)
- अधिकारियों/पदाधिकारियों की आईटी सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण
- आईसीटी सक्षम सेवाएं (जी2जी, जी2ई, जी2सी और जी2बी)
- क्षेत्रीय सूचना-विज्ञान विकास के लिए आईसीटी योजना;
- व्यावसायिक प्रक्रिया की पुनर्रचना

अन्यों के बीच में सेवा प्रोफाइल में शामिल हैः-

- नेटवर्क सेवाएं (वैन, मैन, लैन)
- सरकारी कर्मचारियों के मानव संसाधन विकास के माध्यम से क्षमता निर्माण
- डेटा खनन तथा डेटा भंडारण
- सकल आईसीटी समाधान
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेब सेवाएं
- प्रमाणन प्राधिकरण और पीकेआई सेवाएं
- डोमेन (gov.in) रजिस्ट्रार
- कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट) सेवाएं

- राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र
- निर्णय लेने में सहायता करने के लिए जियोमैटिक्स और सूचना-विज्ञान डिजाइन और विकास
- क्षेत्रीय आईसीटी योजना का प्रतिपादन
- आईसीटी परियोजना परामर्श

एनआईसी के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :-

- सरकारी व्यापार आवंटन (सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, और लेखा और कोषागार आदि) के विभिन्न क्षेत्रों में डोमेन विशेषज्ञता
- प्रणाली विकास अवधि चक्र (एसएलडीसी) में विकास विशेषज्ञता और अनुभव;
- नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता और अनुभव
- सक्रिय साइटों को विकसित करते हुए विशेषज्ञता के साथ वेब साइट का विकास और होस्टिंग करना।
- निकनेट का उपयोग करते हुए ईमेल और इंटरनेट सेवाएं;
- 'मानक उपकरण', कंप्यूटर जागरूकता और अनुप्रयोग प्रणालियों में प्रशिक्षण प्रदान करना
- कार्यान्वयन के दौरान हस्तचालित सहायता प्रदान करना।
- अनुप्रयोग प्रणालियों के लिए राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी समर्थन प्रदान करने वाले जिला केंद्र
- "एनआईसी, शायद एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक एवं तकनीक संगठन है जिसके पास अभिसरण **संचार नामक बिल 2000** जिसमें चार अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के कार्यों का प्रदर्शन करने हेतु बुनियादी ढांचा उपलब्ध है।
- नेटवर्क अवसंरचना सुविधा प्रदाता (एनआईएफपी)
- नेटवर्क सेवा प्रदाता (एनएसपी)
- अनुप्रयोग सेवा प्रदाता (एएसपी)
- सूचना सामग्री एएसपी